भारत सरकार
योजना मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 615
दिनांक 03.12.2025 को उत्तर देने के लिए

सतत विकास लक्ष्य

615. **श्री कौशलेन्द्र कुमार:**

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र ने सितंबर, 2015 में सतत विकस लक्ष्यों को अपनाकर वर्ष 2030 तक पूरे विश्व से गरीबी खत्म करने का वैश्विक लक्ष्य प्राप्त करने की घोषणा की थी; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय एवं
राज्यमंत्री, संस्कृति मंत्रालय

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 25-27 सितंबर 2015 को आयोजित संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में सतत विकास के लिए 2030 के एजेंडे को अपनाया। एसडीजी लक्ष्य 1 'गरीबी उन्मूलन' से संबंधित है। इस लक्ष्य में, अन्य बातों के साथ-साथ, 2030 तक सर्वत्र सभी के लिए अत्यधिक गरीबी का उन्मूलन और राष्ट्रीय परिभाषाओं के अनुसार गरीबी में रहने वाले सभी उम्र के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के अनुपात को कम से कम आधे तक कम करना शामिल है।

(ख) सरकार ने बहुआयामी गरीबी को कम करने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं, जिसमें सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई), प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण), प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य), पीएम उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम), जल जीवन मिशन (जेजेएम), प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई), प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) आदि जैसी योजनाएं शामिल हैं। संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रत्येक योजना को उनके विशिष्ट लक्ष्यों और

बहुआयामी गरीबी के विशिष्ट आयामों के समाधान के लक्ष्यों के साथ डिज़ाइन और कार्यान्वित किया गया है।

उठाए गए इन कदमों के परिणामस्वरूप, नीति आयोग द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट, 'राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक: एक प्रगति समीक्षा 2023' के अनुसार, बहुआयामी गरीबी में जनसंख्या का अनुपात 2015-16 और 2019- 21 के बीच 24.85% से घटकर 14.96% हो गया जो यह दर्शाता है कि इस अवधि के दौरान लगभग 13.5 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं।

इसके अतिरिक्त, नीति आयोग द्वारा प्रकाशित चर्चा पत्र '2005-06 से भारत में बहुआयामी गरीबी' के अनुसार, भारत में बहुआयामी गरीबी 2013-14 के 29.17% से घटकर 2022-23 में 11.28% होने का अनुमान है, जिसका अर्थ है कि इस अवधि के दौरान 24.82 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं। कार्यप्रणाली सहित विवरण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं और https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2023-08/India-National_Multidimentional-Poverty-Index-2023.pdf पर देखा जा सकता है। चर्चा पत्र का विवरण https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2024-01/MPI-22_NITI-Aayog20254.pdf पर देखा जा सकता है।

*****